(b) if so, what steps have been taken by Goverment in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) A team of officers is looking into the complaints made against the management. The report is awaited.

Import of Power Equipments

526. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Electricity Boards in violation of policies enunciated by Government are importing power equipments even though BHEL can manufacture them;

(b) whether it is a fact that State Governments of Uttar Pradesh and Maharashtra have imported power equipment and they are not paying the price of equipment purchased from BHEL;

(c) whether it is a fact that State Electricity Boards are not lifting power equipments from BHEL for which they placed orders; and

(d) if the answers to parts (a), (b) and (c) above be in the affirmative, how the Central Government propose to tackle the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Under the present import policy of the Government, State Electricity Boards are permitted to float global tenders for power equipment irrespective of whether some of the equipment are manufactured indigenously or not. The selection of suppliers on the basis of such global tenders, foreign or Indian, is subject to scrutiny by a Committee set up in the Department of Heavy Industry, which takes into consideration all the relevant factors.

(b) There are some outstanding payments to be made by the U.P. and Maharashtra State Electricity Boards to BHEL towards cost of equipment supplied to them. However, no major equipment has been imported by these Boards recently.

(c) The BHEL had reported some time back about the delay in taking delivery of some equipment by UPSEB. No such report was received in the case of MSEB.

(d) The UPSEB & MSEB have been advised suitably in the matter in so far as outstanding dues/delivery of equipment is concerned.

बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड

527. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापक भ्रष्टाचार, अकुशलता, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा मजदूर संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्डों को भारी घाटा हो रहा है और बिजली के उत्पादन में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप दोनों राज्यों में उद्योग तथा कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये कुछ प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है जिसके कारण हर क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

(1) वर्तमान ताप विद्युत परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादन करना ।

(2) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को शीघ्रतापूर्वक चालू करना।

(3) फालतू विद्युत वाले राज्यों से कम विद्युत वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण करना।

ऊर्जा के स्रोत के रूप में गोबर का इस्तेमाल

528. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा के प्रमुख स्रोत गोबर, कोयला आदि साल में कितनी मात्रा में ईंधन के रूप में जला दिए जाते हैं; और क्या इस ऊर्जा स्रोत को बचाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या गोबर गैस योजना को विकसित करके तथा इस योजना के अन्तर्गत पाखाने का इस्तेमाल आरम्भ करके इस पर आने वाली लागत का 3/4 भाग अनुदान के रूप में देकर ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने का विचार है ताकि इस गैस का इस्तेमाल ईंधन, उर्वरक तथा बिजली के रूप में किया जा सके, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्यमंत्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह): (क) योजना आयोग के ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार 1978-79 में 68.8 मिलियन टन कोयले की कुल वार्षिक खपत में से 5.8 प्रतिशत घरेलू क्षेत्र में उपभोग किया गया था। कोयले के इस्तेमाल में अधिक कुशलता लाकर और मध्यम ग्रेड के और घटिया किस्म के कोयले के इस्तेमाल से गुटिकाओं, कोयला गैस और धुआं रहित कोक जैसे अन्य सस्ते ईंधनों की प्रतिस्थापना से कोयले के संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में उर्जा के प्रयोजनों के लिए वर्ष में एक 73 मिलियन टन गोबर जलाया जा रहा है। खाद आदि के प्रयोजनों के लिए अधिकतम सीमा तक पशु गोबर के संरक्षण की दृष्टि से और साथ ही जैव गैस के उत्पादन के लिए एक धुंआ रहित ईंधन, जो कि जब गैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना है को एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर 1981-82 से हाथ में लिया गया है। इस पर छठी योजना अवधि में 50 करोड़ रुपये का परिव्यय आयेगा।

(ख) जैव गैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अधीन छठी योजना के दौरान लगभग 400,000 पारिवारिक टाइप के जैव गैस यूनिटों की स्थापना करने का विचार है। संयंत्र के आकार और लाभ प्राप्त करने वालों के वर्ग के अनुसार रियायत की नियत राशि लाभ प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जा रही है। रियायत की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

Power equipments produced by BHEL

529. SHRI VITHALBHAI MOTIRAM PATEL: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some State Governments, including Gujarat, have complained against the power generating machinery produced by BHEL;

(b) whether Gujarat Government have requested the Central Government to allow them to import power generating machinery; and

(c) what is the Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Thermal power units at Chandrapur, Rihand and Anpara

530. SHRI SURENDRA MOHAN: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) when were the thermal power units in Chandrapur (Maharashtra), Ri-